पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं.1169

थाना कांड सं.-21 वर्ष-2016 थाना-कृत्यानंद नगर जिला-पूर्णिया, से उत्पन्न

==========

एम.डी. साबीर हुसैन उर्फ मो. साबीर मोहम्मद का बेटा खैरुल हुसैन उर्फ मो. खैरुल निवासी गाँव-चिमनी बाज़ार वार्ड संख्या-33, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

भारतीय दंड संहिता - धारा 376, पॉक्सो अधिनियम - धारा 4-पीड़ित द्वारा अपनी आयु के बारे में दिया गया विरोधाभासी बयान-अभियोजन द्वारा रोके गए शैक्षिक प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य-पॉक्सो प्रावधान के अनुसार पीड़ित की आयु निर्धारित नहीं की गई-पीड़ित के साथ किशोरी जैसा व्यवहार नहीं किया गया-अपीलार्थी को धारा 4 के तहत दोषी ठहरना विधि सांगत नहीं। (कंडिका-11)

आई. पी. सी.-धारा 363 और 376-पीड़ित का अपना साक्ष्य महत्वपूर्ण-तथ्य कॉफी ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं-अपीलार्थी के कृत्यों के खिलाफ विरोध करने के कई अवसरों के बावजूद पीड़ित चुप रही-अपीलार्थी और पीड़ित अच्छी तरह से एक साथ रहते थे-अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई-पीड़ित एक सहमत पक्ष-अविनाश कुमार रंजन बनाम बिहार राज्य, आपराधिक अपील (डी बी) सं. 244/2022-पर निर्भर है। (कंडिका-12,13,14)

सी. आर. पी. सी.-धारा164, साक्ष्य अधिनियम-अधिनियम 145-साक्ष्य के विरोधाभासी पीड़ित का बयान-बयान ठोस साक्ष्य नहीं-अभियोजन पक्ष के आरोप में गंभीर संदेह-डॉक्टर द्वारा शारीरिक हमले की कोई चोट नहीं पाई गई-यौन संबंध में पीड़िता सहमति देने वाला पक्ष-पीड़ित की आयु मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार बड़ी है-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित और वैधानिक नहीं है-निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश दरकिनार कर दिया गया। (कंडिका-15,16,17,18)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं.1169

थाना कांड सं.-21 वर्ष-2016 थाना-कृत्यानंद नगर जिला-पूर्णिया, से उत्पन्न

==========

एम. डी. साबीर हुसैन उर्फ मो. साबीर मोहम्मद का बेटा खैरुल हुसैन उर्फ मो. खैरुल निवासी गाँव-चिमनी बाज़ार वार्ड संख्या-33, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री अमित कुमार झा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, अ.लो.अ.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः24-01-2024

1. अपीलार्थी के विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान अ.लो.अ. को सुना।

2. वर्तमान अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पूर्णिया द्वारा विशेष मामला संख्या 76/2016, सी. आई. एस.346/2017 में पारित दोषी ठहराए जाने के निर्णय दिनांक 09.01.2021 और सजा के आदेश दिनांक 16.01.2021 के खिलाफ दायर की गई है, जो के. नगर थाना कांड संख्या 21/2016 से उत्पन्न होता है, जिसके तहत और जिसमें अपीलार्थी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में पॉक्सो अधिनियम) की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000/-रु. के जुर्माने के साथ सुनाई गई है और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, इसके अलावा छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अपीलार्थी को और दोषी ठहराया गया है और पांच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 25,000/- रुपये का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (संक्षेप में भा.दं.सं.) के तहत दंडनीय अपराध के लिए और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, आगे तीन महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराए जाने के कारण भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत कोई अलग सजा नहीं दी गई है और कारावास की सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी का सार यह है कि सूचक राहुल कुमार राय, जिसे पीड़ित का पिता कहा जाता है, ने 23.01.2016 को के. नगर पी. एस. में एक लिखित आवेदन (प्रदर्श-1/ए) दायर किया। इस आरोप के साथ कि उसकी बेटी (इसके बाद पीड़ित के रूप में संदर्भित), जो पूर्णिया के पूर्णिया इंटर कॉलेज की छात्रा थी, उस समय लगभग 11 बजे कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी और उसके बाद उसने और अन्य लोगों ने पीड़ित की तलाश शुरू की और उस दौरान उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति, नीरज कुमार यादव ने पीड़ित का गलत इरादे से अपहरण कर लिया था और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्ति भी उक्त अपराध में शामिल थे।

4. मुखबिर द्वारा दायर उक्त लिखित आवेदन के आधार पर, नीरज कुमार यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 363,366 ए के तहत कथित अपराधों के लिए के. नगर थाना कांड संख्या 21/2016 वाला औपचारिक प्राथमिकी के. नगर थाना में दर्ज किया गया था और जांच के बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 363,366 ए, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद संबंधित अदालत ने कथित अपराधों का संज्ञान लिया।

5. अपीलार्थी पर भा.दं.सं. की धारा 363,366 ए, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।

6. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ कीः-

(i) पीडब्लू 1- लखन कुमार लाल;

(ii) पीडब्लू 2- मनोज साह;

(iii) पीडब्लू 3- वंदना देवी;

(iv) पीडब्लू 4- जैतुन निशा;

(v) पीडब्लू 5- पीड़ित;

(vi) पीडब्लू 6- राहुल कुमार राय;

(vii) पीडब्लू 7- डॉ. शिवानी सिंह;

(viii) पीडब्लू 8- मो. सलीम; और

(ix) पीडब्लू 9- सुभाष चंद्र मंडल

7. दस्तावेजी साक्ष्य में, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और साबित किया और उन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जो निम्नानुसार हैंः-

(I) प्रदर्श-1-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (इसके बाद दं.प्र.सं के रूप में संदर्भित) के तहत दर्ज किए गए उसके बयान पर पीड़ित के हस्ताक्षर;

(ii) प्रदर्श-1/ए उसके लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर प्रदर्शित करें, जिसके आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत किया गया था।

(iii) प्रदर्श-2-पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट

(iv) प्रदर्श-3-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित का बयान।

8. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अपीलार्थी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को एक निर्दोष व्यक्ति होने का दावा किया और मुख्य रूप से बचाव किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। अपीलार्थी/दोषी ने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

9. विद्वान निचली अदालत ने अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 363,376 और पॉस्को की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 लेकिन अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 366 ए के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया।

10. भा.दं.सं. की धारा 363 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, पीड़ित की उम्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जब यह आरोप लगाया जाता है कि कथित घटना के समय पीड़ित की उम्र 18 वर्ष से कम थी। वर्तमान मामले में पीड़ित के पिता ने अपनी लिखित प्राथमिकी में पीड़ित की उम्र 16 वर्ष बताई है। पीड़ित ने खुद सी. दंड.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करते हुए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी से पहले अपनी उम्र 18 साल होने का खुलासा किया। निचली अदालत के समक्ष, पीड़िता ने अपनी उम्र 16 वर्ष बताई और इस तरह, पीड़िता द्वारा उसकी उम्र के बारे में विरोधाभासी बयान दिए गए। अभि.ग. 7, जिन्होंने पीड़ित की चिकित्सकीय जांच की, ने रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर

पीड़ित की उम्र लगभग 17-18 वर्ष बताई। मान लीजिए, तथाकथित पीड़ित एक कॉलेज जाने वाली लड़की थी जब कथित घटना उसके साथ प्राथमिकी और उसके साक्ष्य के अनुसार की गई थी। इसलिए ऐसी स्थिति में, पीड़ित की उम्र के संबंध में सबसे अच्छा सबूत, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पीड़ित का शैक्षिक प्रमाण पत्र था, लेकिन इस संबंध में, अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए तथाकथित पीड़ित का कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दस्तावेजी सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर पीड़ित की वास्तविक उम्र को छिपाने के लिए रोक दिया गया और यह परिस्थिति पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाती है, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में।

11. पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध को दर्ज करने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि पॉक्सो अधिनियम में दी गई परिभाषा को देखते हुए पीड़ित एक बच्चा है और उक्त परिभाषा के अनुसार, एक बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 के अनुसार पीड़ित की आयु निचली अदालत द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इस अदालत की राय में, इस तरह के प्रावधान का पालन तब किया जाना चाहिए जब पीड़ित की उम्र के बारे में किसी पक्ष द्वारा कुछ संदेह या आपत्ति हो और विशेष रूप से जब शैक्षिक प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य, जिसे आसानी से पेश किया जा सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया जाता है। वर्तमान मामले में पीड़ित द्वारा उसकी उम्र के बारे में विरोधाभासी बयान दिए गए थे, इसलिए निचली अदालत को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पीड़ित की उम्र का पता लगाना चाहिए था और दो साल का लचीलापन हमेशा बच्चे की उम्र में ऊपरी और निचले हिस्से में रहता है जो चिकित्सा राय की मदद से निर्धारित किया जाता है। इसलिए, वर्तमान मामले में, पीड़ित की उम्र को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किए जाने और पीड़ित के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं करने पटना उच्च न्यायालय सी. आर. को रोके जाने के कारण भी से अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तदनुसार, इस अदालत की राय है कि पॉक्सो

अधिनियम में दी गई परिभाषा को देखते हुए पीड़ित को उस समय बच्चे के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब कथित घटना उसके साथ हुई थी। इसलिए, पी. ओ. सी. ओ. अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की सजा कानून की नजर में पूरी तरह से गलत है।

12. अपहरण या अपहरण और बलात्कार के अपराध के संबंध में, जैसा कि वर्तमान मामले में आरोप लगाया गया है, पीड़ित का अपना साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। यह देखने के लिए कि भा.दं.सं. की धारा 363 और 376 के अपराधों के तत्व इस मामले में दर्ज हैं या नहीं, सबसे पहले, मैं निचली अदालत के समक्ष पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्य पर चर्चा करना चाहूंगा।

13. पीड़ित के साक्ष्य के अनुसार, जब कथित घटना उसके साथ हुई तो वह अकेली थी, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से उसके साक्ष्य पर निर्भर करता है। पीड़ित की जांच अभि.ग. 5 के रूप में की गई। उसने कहा कि लगभग 11 बजे, जब वह अपने घर से कॉलेज जा रही थी, तो अचानक उसके पास से गुजर रहा एक सफेद रंग का बोलेरो वाहन रुक गया और उसके बाद अपीलार्थी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे उक्त वाहन के अंदर ले गया और उसके बाद उक्त वाहन की खिड़कियां बंद कर दी गई और तेज आवाज में संगीत शुरू किया गया था। पीड़ित ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने उस पर हमला किया और उसे धमकी दी और उसे पूर्णिया बस स्टैंड पर ले आया और वहाँ से उसे अपीलकर्ता द्वारा एक बस से कटिहार ले जाया गया और वहाँ से वह अपीलार्थी के साथ तीन दिनों के लिए ट्रेन में यात्रा की और उसे किसी ऐसी जगह पर लाया गया जहाँ वह एक कमरे में बंद थी और वह वहाँ एक महीने तक रही और उसके बाद उसे पूर्णिया लाया गया। पीड़ित ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने एक मोहम्मद के घर में किराए पर एक कमरा लिया था। पूर्णिया के मिर्जा हाता में सलीम और वहाँ भी अपीलार्थी ने उस पर हमला किया और उसे धमकी दी और एक दिन उसे अपीलार्थी का मोबाइल फोन मिला, फिर उसने उक्त मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी माँ को सूचित किया और उसके बाद उसके माता-पिता पुलिस के साथ उक्त स्थान पर आए और उसे बरामद कर लिया। पीड़ित ने अपनी जिरह में कहा कि उसने

घर के मालिक की पत्नी से बात की जहां अपीलार्थी ने किराए पर एक कमरा लिया था और किराए के बारे में अपीलार्थी ने उससे बात की थी। उसने जिरह में आगे कहा कि वह लगभग पाँच महीने तक अपीलार्थी के साथ किराए के कमरे में रही और उस अवधि के दौरान उसने घर के मालिक या उसकी पत्नी को अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए गलत कामों के बारे में कुछ नहीं बताया। इन बयानों से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तथाकथित पीड़ित को अपीलार्थी के कृत्यों के खिलाफ विरोध करने के कई अवसर मिले, लेकिन वह चुप रही और जनता के कई व्यक्तियों के सामने अपीलार्थी के आचरण का खुलासा नहीं किया और वह उस घर में पांच महीने तक चुप रही जहां वह घर के मालिक या उसकी पत्नी के सामने अपनी शिकायत उठाने के कई अवसर मिलने के बावजूद पांच महीने तक अपीलार्थी के साथ रही।

14. घर के मालिक, मो. सलीम और उनकी पत्नी की क्रमशः अभि.ग. 8 और अभि.ग. 4 के रूप में जांच की गई। अभि.ग. 8 ने अपदस्थ किया कि अपीलार्थी उसे जानता था क्योंकि वह उसके घर में राजमिस्त्री के रूप में काम करता था, इसलिए उसने अपीलार्थी को अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया और उस समय अपीलार्थी तथाकथित पीड़ित के साथ आया और दोनों लगभग छह महीने तक उसके घर में अच्छी तरह से रहे और उस अवधि के दौरान तथाकथित पीड़ित ने उसके सामने अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह का सबूत अभि.ग. 4 (अभि.ग. 8 की पत्नी) द्वारा दिया गया था। पीड़ित और भौतिक गवाहों के साक्ष्य से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित का कभी अपहरण नहीं किया गया था या उसे कैद में नहीं रखा गया था क्योंकि वह लगभग छह महीने तक चुप रही, जबकि कई मौकों पर उसे जनता या कुछ अन्य व्यक्तियों के सामने अपीलार्थी के कृत्यों का विरोध करने के कई अवसर मिले और यह दर्शाता है कि तथाकथित पीड़ित अपीलार्थी के साथ जाने और उसके साथ लगभग छह महीने तक किराए के कमरे में रहने के लिए एक सहमत पक्ष था और इस संबंध में आप. अपील सं. 2022 की अपील (खंड पीठ) सं. 244 में अविनाश कुमार रंजन बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ। जिस पर अपीलार्थी के विद्वान

वकील ने निर्भरता रखी है, महत्वपूर्ण है। फैसले के पैराग्राफ 29 में किए गए प्रासंगिक अवलोकन को यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"29. यदि ऐसा होता, तो पीड़ित को दो महीने के बाद अपीलार्थी के घर से बरामद नहीं किया जाता। यह उम्मीद करना बहुत अधिक होगा कि पीड़ित केवल कानपुर में एक किराए के आवास में अपीलार्थी के साथ रहने के बारे में मतिभ्रम कर रहा था। इसलिए, यह एक पूर्व निष्कर्ष है कि पीड़ित लगभग दो महीने तक एक अलग स्थान पर अपीलार्थी के साथ था। पीड़ित का कभी अपहरण नहीं किया गया था या उसे कैद में नहीं रखा गया था, जो इस तथ्य से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब उसे कानपुर ले जाया जा रहा था और जब वह अपीलार्थी के साथ किराए के आवास में रह रही थी, तब पीड़ित द्वारा कोई शोर-शराबा नहीं किया गया था। "

15. अभियोजन पक्ष ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान पर भरोसा जताया। पीड़ित ने उक्त बयान में कहा कि लगभग 11 बजे पूर्वाह्न, वह अकेले अपने घर से बाहर आई और मिर्जा चौक पर अपीलार्थी के साथ गई, जहाँ से उसने पहले बस में और उसके बाद ट्रेन में यात्रा की। उक्त कथन पीड़ित द्वारा निचली अदालत के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रूप में उसने अपने साक्ष्य में कहा कि जब वह अपने कॉलेज जा रही थी तो अपीलार्थी ने उसे चार पहिया वाहन के अंदर जबरन खींच लिया था। हालाँकि, दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दिए गए बयान को सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन इस तरह के बयान का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत प्रतिवादी के बयान के विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है। दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान और निचली अदालत के समक्ष उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य के बीच दिखाई देने वाला उक्त विरोधाभास एक भौतिक विरोधाभास है और यह अभियोजन पक्ष के आरोप में गंभीर संदेह पैदा करता है।

16. आरोप के अनुसार, जब पीड़िता अपीलार्थी के साथ रहती थी तो उसे शारीरिक यातना दी जाती थी, लेकिन पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर को उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं मिली। यदि अपीलार्थी बंदी अवधि के दौरान पीड़ित को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था,

तो निश्चित रूप से पीड़ित के शरीर पर शारीरिक हमले के कुछ पुराने संकेत मौजूद हो सकते थे, लेकिन डॉक्टर को ऐसा सबूत नहीं मिला और उक्त परिस्थिति भी अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाती है।

17. प्रदर्श-2, जो कि पीड़ित की चिकित्सा जांच प्रतिवेदन है, के अनुसार वह और विचारण न्यायालय ने इस रिपोर्ट पर भरोसा किया और पीड़ित और अपीलार्थी के बीच यौन संबंध को साबित करने के लिए एक ठोस साक्ष्य के रूप में उक्त चिकित्सा निष्कर्ष को ध्यान में रखा। लेकिन केवल पीड़ित के चिकित्सा परीक्षण के समय गर्भवती होने के कारण, यह नहीं माना जा सकता है कि वह अपीलार्थी के उसके साथ यौन संबंध के कारण गर्भवती हुई थी और इस संबंध में, पीड़ित के अजन्मे बच्चे के साथ अपीलार्थी के पितृत्व को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ अन्य वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस या अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था। यदि हम समझते हैं कि पीड़ित ने अपीलार्थी के उसके साथ यौन संबंध के कारण गर्भधारण किया है, तो भी भा.दं.सं. की धारा 376 का कथित अपराध इस मामले को दर्ज नहीं करता है क्योंकि उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पीड़ित कथित यौन संबंध के लिए एक सहमत पक्ष था और पीड़ित की उम्र के संबंध में सबसे अच्छा सबूत पीड़ित का शैक्षिक प्रमाण पत्र था जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया था और पीड़ित ने उसकी उम्र के बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे। इसके अलावा, पीड़ित की उम्र के संबंध में मेडिकल बोर्ड की राय भी पीड़ित के वयस्क होने की पुष्टि करती है यदि उसकी उम्र के ऊपरी हिस्से को दो साल का लचीलापन दिया जाता है, जो कि उसकी उम्र के संबंध में मेडिकल बोर्ड द्वारा राय दी गई थी।

18. अभियोजन पक्ष के उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्यों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों के आलोक में, इस अदालत ने पाया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और भा.दं.सं. की धारा 363 और 376 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित और कानूनी नहीं है और यह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, तत्काल अपील की

अनुमति दी जाती है और उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा देने वाले विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

19. अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी पहले ही अपनी सजा पूरी कर चुका है, इसलिए उसकी रिहाई के संबंध में कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

20. निर्णय की प्रति को कार्यवाही और आवश्यक जानकारी के लिए विद्वत विचारण न्यायालय को भेजा जाए।

21. निचली अदालत का अभिलेख को विद्वत विचारण न्यायालय में वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।